



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण सं. 36/2022

[आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण, रायपुर बेंच, रायपुर द्वारा आईटीए संख्या 29/आरपीआर/2021 में

पारित दिनांक 11.10.2021 के आदेश से उत्पन्न]

आयकर अधिकारी-3 (1) रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

---अपीलकर्ता

बनाम

सिल्फी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, कमरा संख्या 7, भूतल, जीवन प्लाजा, लोधी कंडिका चौक के पास,  
रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :- श्री अजय कुमारानी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :- श्री नीलाभ दुबे, अधिवक्ता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा श्री जितेंद्र साहू,  
अधिवक्ता।

युगल पीठ :

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीश



पीठ पर निर्णय

(08.04.2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षिप्त में अधिनियम, 1961) की धारा 260 ए के तहत यह अपील प्रस्तुत कर निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न तैयार करके सुनवाई के लिए स्वीकार कि गयी :---

“क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत पारित प्रधान आयकर आयुक्त के पुनरीक्षण आदेश को अपास्त करना उचित था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने के लिए करदाता को सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया था?”

2. उपर्युक्त विधि का प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर उत्पन्न हुआ है:---

(i) यहां उत्तरवादी अर्थात् करदाता एक कंपनी है जो स्पंज आयरन और एमएस सिल्लियों के विनिर्माण और विक्रय में लगी हुई है और कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए, इसने 27.09.2015 को 7,99,351/- की कर योग्य आय घोषित करते हुए अपना रिटर्न प्रस्तुत किया और उसके बाद, अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत रिटर्न संसाधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रु 8,44,800/- की मांग हुई।

(ii) अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत 29.12.2017 को मूल्यांकन पूरा किया गया और अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट के कारण अधिनियम, 1961 की धारा 68 के अंतर्गत मूल्यांकन अधिकारी (ए.ओ.) द्वारा 9,00,00,000/- की वृद्धि की गई।

(iii) प्रधान आयकर आयुक्त (संक्षिप्त रूप में “पीसीआईटी”) ने अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू की और 26.03.2021 को आदेश पारित किया गया। जिसमें पीसीआईटी द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि ए.ओ. का आदेश राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है और पीसीआईटी ने ए.ओ. को नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है।

(iv) अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत पीसीआईटी के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, करदाता/उत्तरवादी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षिप्त रूप में ‘आईटीएटी’) के समक्ष संपर्क किया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने करदाता/उत्तरवादी के पक्ष में अपील स्वीकार कर ली है, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपीलकर्ता/राजस्व ने अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की है।



3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमरानी ने यह प्रस्तुत किया कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा करदाता/उत्तरवादी के पक्ष में अपील स्वीकार करना पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि अधिनियम, 1961 की धारा 263 के अंतर्गत अपेक्षित सुनवाई का उचित अवसर उत्तरवादी को प्रदान किया गया था, इसलिए वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा विधि के प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में दिया जाना चाहिए।

4. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री नीलाभ दुबे और श्री जितेन्द्र साहू ने प्रस्तुत किया कि पीसीआईटी द्वारा पारित आदेश अधिनियम, 1961 की धारा 263 के विरुद्ध है और आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अमिताभ बच्चन 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है, इसलिए वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण ने उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण निवेदन पर विचार किया है और अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया है।

6. इस स्तर पर, अधिनियम, 1961 की धारा 263 के दायरे पर ध्यान देना उचित होगा।

7. अधिनियम, 1961 की धारा 263, निचले प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के संबंध में प्रधान आयुक्त/आयुक्त को संशोधन की पर्यवेक्षी शक्ति प्रदान करती है। यद्यपि, यह शक्ति सख्त क्षेत्राधिकार संबंधी शर्तों से बंधी हुई है। आयुक्त किसी मूल्यांकन आदेश को केवल तभी संशोधित कर सकता है जब:

– (क) आदेश "त्रुटिपूर्ण" हो, और (ख) यह "राजस्व के हितों के लिए हानिकारक" है। ये दोनों स्थितियाँ संयुग्म हैं अर्थात् शक्ति का प्रयोग करने से पहले दोनों को पूरा किया जाना चाहिए। यदि इनमें से किसी भी तत्व की कमी है, तो आयुक्त को संशोधन करने का अधिकार नहीं मिलता है।

8. इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय के उनके माननीय न्यायाधीशों ने मालाबार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, केरल राज्य 2 के मामले में आधिकारिक रूप से व्याख्यायित किया और यह अभिनिर्धारित किया है कि "यदि आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं है, लेकिन राजस्व के लिए हानिकारक है, या यदि यह त्रुटिपूर्ण है, लेकिन राजस्व के लिए हानिकारक नहीं है, तो अधिनियम, 1961 की धारा 263 को लागू नहीं किया जा सकता है"। दूसरे शब्दों में, विधि और तथ्यों के संभावित या अनुमेय दृष्टिकोण को दर्शाने वाले मूल्यांकन आदेश को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वह आयुक्त को पसंद नहीं है।

9. इसके अलावा, राजस्व की हर हानि, अपने आप में, राजस्व के लिए "प्रतिकूल" नहीं है, यह एक त्रुटिपूर्ण आदेश का परिणाम होना चाहिए। इसके विपरीत, एक त्रुटि जिसका राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पुनरीक्षण को ट्रिगर नहीं कर सकती है। अधिनियम, 1961 की धारा 263 के संदर्भ में एक "त्रुटिपूर्ण" आदेश तब माना जाता है जब वह विधि में मान्य योग्य न हो, अर्थात्, जब उसमें विधि का त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग या तथ्यों का



स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण मूल्यांकन शामिल हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई आदेश केवल इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं है क्योंकि आयुक्त की मामले पर अलग राय है।

10. सीआईटी बनाम गेब्रियल इंडिया लिमिटेड 3 के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पाया कि यदि आयकर अधिकारी (आईटीओ/एओ) ने किसी विशेष विवादक के संबंध में परीक्षण किया है, जवाब प्राप्त किए हैं और फिर एक दृष्टिकोण अपनाया है, तो केवल इस तथ्य से कि एओ के आदेश में विवादक पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है या आयुक्त निष्कर्ष से असहमत हैं, आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं बना देता है और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:---

"आईटीओ के निष्कर्ष को सिर्फ इसलिए 'गलत' नहीं कहा जा सकता क्योंकि कमिश्नर उससे सहमत नहीं हैं। एओ के आदेश को सिर्फ इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसमें विस्तृत चर्चा नहीं की गई।"

11. इस हितकारी सिद्धांत को लगातार बरकरार रखा गया है, जिसका अर्थ है कि जहां ए.ओ. ने अपना मस्तिष्क लगाया है (भले ही संक्षेप में) और एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा है, पुनरीक्षण प्राधिकारी अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसका एक अलग दृष्टिकोण है या क्योंकि वह आदेश में अधिक विस्तृत तर्क की अपेक्षा करता है। अन्यथा निर्णय लेने से पुनरीक्षण शक्ति अपीलीय पुनरीक्षण में परिवर्तित हो जाएगी, जो इसका उद्देश्य नहीं है।

12. अधिनियम, 1961 की धारा 263 में प्रावधान के अनुसार राजस्व के हितों के लिए हानिकारक, जिसका आम तौर पर अर्थ यह है कि त्रुटि के कारण कर राजस्व की हानि हुई है (कर का कम लगाया जाना) या राजस्व की उचित कर एकत्र करने की क्षमता के लिए संभावित खतरा पैदा किया है। यदि त्रुटि का कर योग्य आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है (उदाहरण के लिए, एक प्रक्रियात्मक अनियमितता जो कर गणना को प्रभावित नहीं करती है), तो पुनरीक्षण उचित नहीं है।

13. **मालाबार इंडस्ट्रियल कंपनी (सुप्रा)** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरण देकर इस वाक्यांश की व्याख्या की: - "यदि आईटीओ कार्यवाही के दो स्वीकार्य तरीकों में से एक को अपनाता है और परिणाम राजस्व की हानि होती है, या जहां दो दृष्टिकोण संभव हैं और आईटीओ करदाता के पक्ष में एक को अपनाता है, तो ऐसे आदेश को राजस्व के लिए प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है जब तक कि अपनाया गया दृष्टिकोण विधि में अस्थिर न हो। इस प्रकार, राजस्व हानि की कुछ सीमा तक भी सहन की जा सकती है, यदि यह ए.ओ. द्वारा निर्णय के वैध प्रयोग से उत्पन्न होती है। केवल तभी जब ए.ओ. का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत हो या करदाता के दावे की स्वीकृति किसी भी साक्ष्य पर आधारित न हो, आदेश पूर्वाग्रहपूर्ण हो सकता है, जिसमें सुधार की आवश्यकता हो।

14. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि करदाता के आदेश के विरुद्ध पीसीआईटी ने अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए 11.03.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और



15.03.2021 को अपराह्न 1:53 बजे उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें करदाता को अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत कारण बताने की आवश्यकता थी कि अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत इस प्रकार तैयार किए गए आरोपित कर निर्धारण को क्यों न संशोधित/अपास्त किया जाए, यह मानते हुए कि ऐसा आदेश राजस्व के हित के लिए हानिकारक होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि सुनवाई की तारीख भी 15.03.2021 को शाम 4:00 बजे निर्धारित की गई थी। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि 15.03.2021 को, करदाता अपने सर्वोत्तम ज्ञात कारणों से उपस्थित नहीं हुआ और उसके बाद, 26.03.2021 को अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह राजस्व के हित के लिए हानिकारक है। उक्त आदेश को करदाता द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि पीसीआईटी द्वारा अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत पारित आदेश विधि के अनुसार नहीं है और यह अधिनियम, 1961 की धारा 263 में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है, क्योंकि करदाता/उत्तरवादी को सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया था और साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि ए.ओ. की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण नहीं है। इस प्रकार, हालांकि पीसीआईटी ने ए.ओ. के आदेश को त्रुटिपूर्ण पाया है, क्योंकि यह राजस्व के हित के लिए हानिकारक है, लेकिन अधिनियम, 1961 की धारा 263 में निहित प्रावधानों के प्रकाश में करदाता/उत्तरवादी को अपना बचाव करने के लिए सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया और, इसलिए, पीसीआईटी का आदेश रद्द/अपास्त किए जाने योग्य है।

15. उपर्युक्त चर्चा के तहत, हमारा विचार है कि, पीसीआईटी द्वारा पारित आदेश अधिनियम, 1961 की धारा 263 में निहित प्रावधानों के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि करदाता को सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया था और अमिताभ बच्चन (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों के आलोक में भी। चूंकि पीसीआईटी द्वारा अधिनियम, 1961 की धारा 263 के तहत एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था, जिसमें करदाता/उत्तरवादी को नहीं सुना गया था, इसलिए पीसीआईटी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि यह आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह राजस्व के हित के लिए हानिकारक है, अभिलेख के आधार पर उचित निष्कर्ष नहीं है और इसलिए, इसे आईटीएटी द्वारा उचित तरीके से खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, हमें वर्तमान कर अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है। परिणामस्वरूप, विधि के प्रश्न का उत्तर करदाता के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध दिया जाता है। परिणामस्वरूप, कर प्रकरण खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है, तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।



कर प्रकरण सं. 36/2022

2025: सीजीएचसी.16499-डीबी

6

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(दीपक कुमार तिवारी)

न्यायाधीश





**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

